भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5124
(जिसका उत्तर सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक) को दिया जाना है)

देश में ऋण योग्यता

5124. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री प्रतापराव जाधवः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ता

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वैश्विक महामारी के बाद से देश की आर्थिक मैट्रिक/ऋण योग्यता में काफी सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के अधिकारियों के साथ कोई बैठक की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) देश को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष और अगले तीन वर्षों के लिए जीडीपी के प्रति राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास की वृद्धि हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) जी, हाँ। महामारी के दौरान भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है। महामारी की अवधि में प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित/संपुष्ट रेटिंग अनुबंध I में संलग्न है। भारत की सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि और बाहरी झटकों के प्रति लचीलापन बेहतर सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल के प्रमुख कारक रहे हैं।

(ख) एवं (ग) जी, हाँ। भारत सरकार समय के साथ भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) के साथ तत्परतापूर्वक जुड़ी रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों, नवीनतम आर्थिक घटनाक्रमों, विकास परिप्रेक्ष्य, राजकोषीय समेकन और सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में सीआरए को संवेदनशील बनाने के लिए सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवधिक ऋण समीक्षा बैठकों के दौरान, पारदर्शिता आवाहन और आउटरीच के ठोस प्रयास किए गए हैं।

(घ) राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत और बजट अनुमान 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा, सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे

के स्तर तक कम करने के अपने इरादे की घोषणा की है। फिर भी, निरंतर वैश्विक अनिश्चितता के संदर्भ में, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण में वित्त वर्ष 2023-24 में किसी भी मध्यम अवधि के राजकोषीय अनुमानों को रेखांकित नहीं किया गया है।

(ङ) भारत सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें पूंजीगत व्यय परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार शामिल हैं।

*****

अनुबंध I

महामारी के दौरान प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित/संपुष्ट रेटिंग

रेटिंग एजेंसी	वर्ष	विदेशी मुद्रा		स्थानीय मुद्रा		टिप्पणियां
		रेटिंग	दृष्टिकोण	रेटिंग	दृष्टिकोण	
मूडी	2022	बीएए3	स्थिर	बीएए3	स्थिर	2021 में दृष्टिकोण नकारात्मक से सुधरकर स्थिर हो गया
	2021	बीएए3	स्थिर	बीएए3	स्थिर	
	2020	बीएए3	नकारात्मक	बीएए3	नकारात्मक	
फिच	2022	बीबीबी-	स्थिर	बीबीबी-	स्थिर	2022 में दृष्टिकोण नकारात्मक से सुधरकर स्थिर हो गया
	2021	बीबीबी-	नकारात्मक	बीबीबी-	नकारात्मक	
	2020	बीबीबी-	नकारात्मक	बीबीबी-	नकारात्मक	
एस एंड पी	2021	बीबीबी-	स्थिर	बीबीबी-	स्थिर	दृष्टिकोण अपरिवर्तित रहा है।
	2020	बीबीबी-	स्थिर	बीबीबी-	स्थिर	